गलतियों की आदी-मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भावी कार्यक्रम की विवेचना

यह भी कहा गया है कि संसदीय राजनीति और चुनावों के चक्कर में जन संघर्षों और पार्टी को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वास्तव में चुनाव लड़ने और संसद का अपने प्रचार के लिये उतना उपयोग नहीं किया गया जितना किया जा सकता था। होना तो यह चाहिये था कि सभी जन संघर्षों को चुनाव को ध्यान में रखकर लड़ा जाना चाहिए था क्योंकि राजसत्ता प्राप्त करना ही सभी संघर्षों का अन्तिम लक्ष्य है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 21 वी. कांग्रेस में चर्चा के लिये 'राजनीतिक-रणनीतिक लाईन' और 'राजनतिक प्रस्ताव' के ड्राफ़्ट जारी किये हैं। उनको पढकर लगता है कि अब भी शतुरमुर्ग की तरह पार्टी रेत में सिर गड़ाकर कई सच्चाइयों से मुंह छुपा लेना चाहती हैं।

राजनीतिक-रणनीतिक लाईन के ड्राफ्ट में पार्टी ने माना है कि 'थर्ड फ्रन्ट' के दिन अब लद गये हैं और पार्टी को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिये संघर्ष करना चाहिये हालांकि 'वाम जनतांत्रिक मोर्चे' का लक्ष्य अभी भी कायम रखा गया है। पार्टी ने माना है कि 1996-98 में सरकार को बचाये रखने के चक्कर में संघर्ष विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन गलतियों को दोराने की आदी पार्टी ने 2004-09 तक मनमोहन सरकार के साथ भी इस तरह सहयोग किया जैसे वो एक कम्युनिस्ट सरकार हो जिसको चलवाये रखना उन्हीं की जिम्मेवारी थी पार्टी ने न्यूकलियर उर्जा मुद्दे पर सरकार छोड़ने को सही ठहराते हुये लिखा है कि यह मुद्दा वास्तव में अमरीका से रणनीतिक सहयोग बढाने का था इसलिये इस मुद्दे पर सरकार से अलग होना तो ठीक था लेकिन सरकार से यह समर्थन वापसी न्यूकलियर उर्जा पर आई. ए. ई. ए. से बातचीत शुरू करते ही हो जानी चाहिए थी। जबकि वास्तविकता यह है कि देश की अधिसंख्य जनता अब भी यह मानती है कि न्यूकलियर समझौते से देश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा।

पार्टी के लिये ज्यादा उचित होता कि वह मंहगाई और मज़दूर विरोधी क़ानूनों के विरोध में सरकार से समर्थन वापिस लेती और उसके बाद न्यूकलियर समझौते को अमरीका के सामने समर्पण और अन्ततोगत्वा मंहगाई आदि कारणों के रूप में पेश करती।

यह भी कहा गया है कि संसदीय राजनीति और चुनावों के चक्कर में जन संघर्षों और पार्टी को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वास्तव में चुनाव लड़ने और संसद का अपने प्रचार के लिये उतना उपयोग नहीं किया गया जितना किया जा सकता था। होना तो यह चाहिये था कि सभी जन संघर्षों को चुनाव को ध्यान में रखकर लड़ा जाना चाहिए था क्योंकि राजसत्ता प्राप्त करना ही सभी संघर्षों का अन्तिम लक्ष्य है। लेकिन यहां तो जन संघर्षों का चुनावों से कोई ठीक तालमेल ही नहीं था बल्कि उत्तर के राज्यों में तो लोगों ने पार्टी को सिर्फ संघर्ष के लिये ही इस्तेमाल किया और वोट नहीं दिये। वास्तव में जन संघर्ष और चुनाव व संसद एक दूसरे के पूरक हैं। संसद सत्र के समय पार्टी के संसद सदस्यों को पोलिटब्यूरो द्वारा निर्देशित करने व संघर्षों को संसद में उचित तरीके से उठाने जैसे मुद्दों पर भी ड्राफ्ट खामोश है।

राजनीतिक प्रस्ताव, एक राजनैतिक समूह के रूप में माओवादियों के बारे में मौन है तो 'आप' पार्टी को स्पष्ट घोषणा के अभाव में बुर्जुआ पार्टी मानने से बचा गया है। जबकि राजनीति का नौसिखिया भी बता सकता है कि पूंजीपति वर्ग 'आप' पार्टी के मोदी को फेल होने के बाद सत्ता संभालने के लिये तैयार कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल तो फिक्की (भारतीय उद्योगपतियों का परिसंघ) और पूंजीपतियों के कई अन्य मन्चों पर उन्हें अच्छी तरह आश्वस्त कर चुके हैं कि नीतिगत कोई परिवर्तन नहीं किये जायेंगे। यानि कि सिर्फ लिपिस्टक बिन्दी के अलावा चेहरा वही रहेगा। फ़िर भी आप से कोई आशा लिये बैठे रहना तो अपनी अकर्मण्यता को छुपाना ही होगा।

पार्टी अपने प्रस्ताव में बी.जे.पी. के हिन्दूत्व के एजेन्डे से लड़ने की भी बात करती है जबकि वास्तविकता यह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का काम तो बी जे पी अन्दर ही अन्दर लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरा कर चुकी है। नये-नये मुण्डे हुये हिन्दुओं ने ही वोट देकर बीजेपी को लोकसभा में विजय दिलायी। यहां तक कि परंपरागत रूप से धर्म से ज्यादा अपनी जाति पर गर्व करने वाले उत्तरी भारत के एक बड़े समूह-जाटों, ने भी हिन्दू धर्म के नाम पर बी.जे.पी. को वोट दिया। अब तो बी जे पी सिर्फ़ इस ध्रुवीकरण को पुख्ता और स्थायी बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगर माकपा को भाजपा के हिन्दूवादी ऐजेन्डे से मुकाबला करना है तो उसे लोग़ों को आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई में उतारना होगा। उसी संघर्ष में ही लोग यह समझ पायेंगे कि भाजपा ने कैसे उन्हें हिन्दू के नाम पर मूर्ख बनाया है और पूंजीपतियों का हित साधा है। सबसे बड़ा द्वन्द पार्टी के सामने ये है कि चुनावी राजनीति करते हुये भी कैसे वो लोगों को आमूल चूल परिवर्तन के लिये तैयार करे।

मोदी और भाजपा जैसी फासिज्म की तरफ़ बढती तोक़तों, जो अमरीकी साम्राज्यवाद से गठजोड़ करके और भी क्रूर हो चुकी हैं, उनके शासन में कैसे जनतान्त्रिक ढंग से संघर्ष को सफलता पर पहुंचाये। अगर पार्टी इस संघर्ष में आम जनता को लगातार और मिलिटेन्ट बनाते हुये आगे बढती रहेगी तो मोदी के बाद पांच साल केजरीवाल के नहीं बल्कि लाल सलाम के होंगे अन्यन्था कत्लेआम के।

-अजातशत्रु

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के लिखे पिछले अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। मोदी सरकार द्वारा श्रम सुधार के नाम पर श्रमिक विरोधी कार्यों के संदर्भ में लेख 'ताकि मेडिकल का फले-फूले व्यापार-ई एस आई 'बंधकों' को मुक्त करेगी सरकार', 'पी पी पी मोड की तैयारी' तथा 'भविष्य निधि से श्रमिकों को वंचित करने की ओर' द्वारा मज़दूरों की लाचारी और बदहाली का समाचीन वर्णन किया गया है।

मोदी सरकार ने पिछली यूपीए सरकार से भी दो कदम आगे बढकर जन कल्याणकारी कार्यों से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और विकास के नाम पर कॉरपोरेट जगत को मुनाफ़ा कमाने की हर सम्भव छूट दी जा रही है। बीमा कम्पनियां तथा तथाकथित सुपर स्पैशलिस्ट अस्पताल के मालिक मेडिक्लेम के ज़रिए फ़ल-फूल रहे हैं। केन्द्र सरकार ने अपने बजट में मेडिक्लेम के लिये जो प्रावधान रखे हैं उनसे इन असपतालों की बांछें खिल उठी हैं। सरकार, बीमा कम्पनियों तथा निजी अस्पतालों की आपसी सांठ-गांठ से यह गोरखधंधा चलता रहता है। मेडिक्लेम की किश्तों की राशि इतनी ज़यादा होती है कि आम आदमी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता।

दूसरी तरफ़ इन अस्पतालों में इलाज का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो इन अस्पतालों के बिल की राशि इतनी ज्यादा होती है कि मरीज़ों को मेडिक्लेम की राशि के अलावा अपनी जेब से भी भुगतान करने को मज़बूर होना पड़ता है। आजकल इन अस्पतालों में खाड़ी देशों की मरीज़ों की संख्या बढ रही है जिनके लिये इन खर्चों का भुगतान करना कठिन नहीं होता। समस्या तो अपने देश की आम जनता की है जो इन अस्पतालों की तरफ़ झांक भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त मज़दूरों क्के वेतन से साढे 6 प्रतिशत काटकर एकत्रित हुई राशि से ई एस आई निगम मज़दूरों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं कराता जिसके वे पूरे हक़दार हैं। मोदी सरकार विकास व सुधारों की बात तो बहुत करती है परन्तु व्यवहार में निगम द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति कोताही करने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती।

गौरतलब है कि यदि निगम अपने अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को कुशलता से चला ले तो मज़दूरों को चिकित्सा सेवाऐं मिल जाएगी और निजी अस्पतालों की लूट-खसोट पर भी कुछ हद तक अंकुश लग जाएगा, परंतु इसके लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त श्रम सुधार के नाम पर श्रमिक हितों संबंधी अधिनियमों व क़ानूनों में संशोधन करके उद्योगपतियों व पूंजीपतियों को उनका मुनाफ़ा बढाने व मज़दूरों का शोषण करने की खुली छूट दी जा रही है।

एक अन्य लेख 'शर्मनाक-इलाज कराने लखनऊ से गुड़गांव पहुंचे मुलायम' के ज़रिए गुड़गांव स्थित सुपर स्पैशलिटि अस्पतालों के सिरमौर मेदांता अस्पताल व हृदय विशेषज्ञ तथा मार्केटिंग में माहिर डॉ.नरेश त्रेहन द्वारा शासक वर्ग तथा धन्ना सेठों को दी जा रही उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित वर्णन किया गया है। जेल की सज़ा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री औम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अभय चौटाला जब इच्छा हो तब जेल से बिमारी के नाम पर स्वास्थ्य लाभ के लिये मेदांता अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉ. त्रेहन उन्हें हर प्रकार के सुविधाऐं प्रदान करते हैं। सुनने में आया है कि औम प्रकाश चौटाला ने इस अस्पताल को बनाने में काफ़ी सहायता की थी।

भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत प्राप्त करने बाद 'आप' के शीर्ष नेताओं में चल रही जूत-पैजार व आपके संयोजक तथा सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल की विवादास्पद कार्यशैली का 'खबर दार-आप कहीं कांग्रेस न हो जाये' तथा 'किसका भला करेगी आम आदमी पार्टी' लेखों में सटीक विश्लेषण किया गया है। वास्तव में 'आप' ने अपनी विचारधारा कभी स्पष्ट नहीं की और मुद्दों पर आधारित राजनीति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य रहा है।

केजरीवाल की कार्यशैली भी संसदीय शासन प्रणाली के अपेक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति व नरेन्द्र मोदी तथा इंदिरा गांधी की तर्ज़ पर चलने की है, जबकि दूसरी तरफ़ केजरीवाल लोकतंत्र व स्वराज तथा पारदर्शिता की बात करते हैं। इस विरोधाभास के चलते पार्टी में आन्तरिक कलह व संघर्ष होना स्वाभाविक है।

सी बी आई के पूर्व प्रमुख जोगिंदर सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद से उनकी राष्ट्रीयता पूछने के लेख के संबंध में उनके इरादे पर स्तम्भ 'तुर्की-ब-तुर्की' द्वारा उपयुक्त कटाक्ष किया गया है। मोदी सरकार की कथनी व करनी में अंतर तथा मोदी के भारत निर्माण के वायदे की असलियत का।

'मनरेगा योजना में कटौती का प्रसताव' के ज़रिए पर्दाफ़श किया गया है। लोकसभा में नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि वह मनरेगा को समाप्त कहीं करेंगे क्योंकि मनरेगा यूपीए सरकार की विफलता का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसके विपरित मोदी सरकार मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर क़ानून में संशोधन करके कटौती करने जा रही है जिसका असर गरीब मज़दूरों व बेरोजगारों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा। जबकि पहले मनरेगा के कारण मज़दूरों का अन्य राज्यों से पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पलायन रूक गया था। मोदी का नारा 'सब का साथ सब का विकास' थोथा रह गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी उच्च कोटि के तथा प्रेरणादायक है।

प्रो. जुगल किशोर गुप्ता

तुर्की-ब-तुर्की

आजम खां ''मीडिया वाले अपराधियों की तरफ़दारी करते हैं।'' (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई. टी. एक्ट की धारा 66ए निरस्त किये जाने पर)

हमारा कहना है:-

- आपकी झल्लाहट समझ में आती है रामपुर के मुख्य मंत्री आज़म खां साहब! कुछ दिन पहले ही तो ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र को आपके आदेश पर रामपुर पुलिस ने आई. टी. एक्ट की इसी धारा के अन्तर्गत जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। हालांकि उस नाबालिग का कसूर इतना भर था कि उसने फ़ेसबुक पर आपको लेकर सवाल उठाने की हिमाकत की थी। आपने तब बड़े गर्व से मीडिया को कहा था कि हमें अपराधियों को फ़टाफ़ट सबक सिखाना आता है। सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले ने अब आपको ही सबक सिखा दिया।
- अगर उस नाबालिग लड़के ने आपको गलत ढंग से उद्धर्त किया भी था तो भी आप मामले की बाकायदा तफ़्तीश होने देते, सबूत और सफ़ाई भुजारने देते और तब दोष सिद्ध होने की हालत में आगे कानूनी कार्यवाही करते। पर आपने तो आई. टी. एक्ट की तानाशाही धारा 66 ए का सहारा लिया, जिसके अनुसार 'ग़लत' बात पोस्ट करने पर तुरन्त गिरफ़्तारी का प्रावधान था। जाहिर है ग़लत क्या है, यह आप जैसे सत्ताधारी अपने हिसाब से ही तय कर लेते हैं। गनीमत है सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले ने आप जैसों से यह 'सुविधा' छीन ली है।
- वैसे आप न पहले और न ही अकेले राजनीतिक प्राणी हैं जिसे इस एक्ट का दुरूपयोग करने का लाइसेंस रास आया हो। महाराष्ट्र में शिवसेना के सर्वोच्च गुंडे बाल ठाकरे के निधन पर उसके लग्गुओं-भग्गुओं द्वारा सारे महाराष्ट्र को जबरन बंद करा दिया गया था। इस पर एक स्कूली छात्रा ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया और एक अन्य ने उसकी बात को पसन्द किया तो दोनों को जेल भेज दिया गया। घोटालों में संलिप्त जूनियर चिदम्बरम (पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का बेटा) से लोग़ों ने फ़ेसबुक पर सवाल क्या पूछ लिये, उसने भी इसी धारा की शरण ली। और भी कितने ही हैं। कांग्रेस और भाजपा तो खैर फ़ैसले के बाद थूक कर चाटने का काम कर चुके हैं, पर शरद यादव जैसे आपकी ही तरह तिलमिला रहे हैं।
- बोलने की आज़ादी और विचारों की स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का यह एतिहासिक फ़ैसला आया है। इतिहास के कूड़ेदान में जाने को तत्पर आज़म खां जैसे लोग ही इसका विरोध कर सकते हैं। देश के तमाम नागरिकों ने फ़ैसले का दिल खोल कर स्वागत किया है।